4 Cr: PG IV Sem

अध्याय - 23

(1)

दवाब समूह की भूमिका भारत के विशेष संदर्भ में
(Role of Pressure Groups with Special Reference to India)

हमने राजनीतिक दल कि अवधारणा और महत्व की व्याख्या की तो यह स्पष्ट है कि दवाब समूह की भूमिका भी समझना होगा क्योंकि दवाब समूह एक वैसा संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के संदर्भ को, सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किये बिना भी, प्रभावित करना चाहता है। खासकर भारत में और अमेरिका में दवाब समूहों कि भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दवाब समूह संसद की लॉबी में बैठकर किसी खास विषय पर सांसदों को प्रभावित करते हैं। फिर भी इनका तमाम कार्य "राष्ट्रहित में न होकर किसी विशेष हित में होता है" जैसे भारत में INTUC या किसान सभा या बिहार में FUSTAB, ABVP इत्यादि।

वास्तव में ये दवाब समूह आगे चलकर राजनीतिक दल बन जाते हैं।

इस संबंध में अब हम विवेचित करेंगे की भारत में दवाब समूह की अवधारणा क्या है, विभिन्न प्रकार क्या है और उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में क्या है।

अवधारणा — Odegard ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "American Government" में लिखा है, "दवाब समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हैं और घटना क्रम को, विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को, इसलिये प्रभावित करने का प्रयत्न करें कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि दवाब समूह अपने हितों की रक्षा के लिये सरकार पर अनुकूल कानून निर्माण के लिये दवाब डालते हैं। इनका उद्देश्य किसी खास विषय से रहता है जैसे 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी

Scanned with CamScanner

भारत में दवाब समूह की विशेषताएँ

(Characterestics of pressure groups in India)

(a) Robert L. Hargrawe ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "India : Government and Politics in a Developing Nation" में भारत में दवाब समूहों की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं

प्रथम, भारत में दवाब समूह का विकास निम्न गति से हुआ है। जो दवाब समूह विद्यमान हैं वे काफी कमजोर हैं।

द्वितीय, चूंकि दवाब समूह शक्तिशाली नहीं है अतः प्रशासन पर उनकी पहुँच भी कम है। वे सरकार को निचोरने वाली शक्ति मानते हुए यथासम्भव उससे अलग रहना चाहते हैं।

तृतीय, कांग्रेस दल के भीतर पाये जाने वाले विभिन्न गुटों में विशिष्ट हितों Agent के रूप मे कार्य किया है।

चतुर्थ, अधिकांश भारतीयों की राजनीतिक क्षमता निम्न स्तर की है और ये लोग सरकारी पदाधिकारी को अनुत्तरदायी और भ्रष्ट मानते हैं। दूसरी ओर सरकारी पदाधिकारियों में भी दवाब समूहों की गतिविधियों के प्रति आशंका बनी रहती है।

(b) डॉ. रजनी कोठारी के अनुसार भारत में दवाब समूह की निम्न विशेषताएँ हैं —

प्रथम, भारत में हित और वर्ग की अधिकता के कारण इनका प्रतिनिधित्व दलों द्वारा होता है।

द्वितीय, यद्यपि भारत में वाणिज्य संघों, मजदूर संघों या अध्यापक संघों आदि की राष्ट्रीय संस्थाएँ भी हैं किन्तु राष्ट्रीय राजनीति में वे प्रभावशाली नहीं हैं, फलतः इनके सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल होते हैं।

Scanned with CamScanner

दवाब समूह की भूमिका भारत के विशेष संदर्भ में

तृतीय, भारत में वर्गों या हितों का विकास परम्परागत व्यापारिक परिवारों और समूहों के द्वारा हुआ है।

चतुर्थ, भारत में वर्ग या हित का संगठन आर्थिक या सामाजिक आधार पर न होकर जाति पांति के आधार पर हुआ है।

पंचम, भारत में आर्थिक मांगों को तभी माना जाता है जब वे राजनीतिक ढंग से उठाये जायें। जिन हितों को कोई राजनीतिक दल उठाने को तैयार नहीं होता है तो जनता हिंसात्मक रूप ले लेती है।

भारत में दवाब समूह के उपर्युक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि यहाँ दवाब समूह उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में है। दवाब समूहों जैसे मजदूर संघ आदि का राजनीति में भाग लेना भारत में अच्छा नहीं माना जाता है। भारत में दवाब समूह के कम प्रभावशाली होने का एक अन्य कारण यह है कि यहाँ परिवर्तन और आधुनिकीकरण का माध्यम सरकार है, इसलिये विभिन्न हित या वर्ग राजनीतिक दलों या गुटों के माध्यम से ही सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। STOP

Scanned with CamScanner

अकाली दल, द्रविड़ मुनत्र कड़गम

आधुनिक दवाब समूह (Modern Pressure Groups) — आधुनिक दवाब समूह के अन्तर्गत निम्न दवाब समूह आते हैं

(i) **व्यापारिक दवाब समूह** — भारत में अनेक व्यवसायिक समूह भी दवाब समूहों का कार्य करते हैं इसमें विभिन्न व्यवसायिक घरानों जैसे टाटा, डालमिया आदि राजनीतिक दलों को उपहार देकर, अपने समर्थक प्रत्याक्षी को निर्वाचन में विजयी बनाकर आदि माध्यम से सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक व्यापारिक संगठन हैं जो सार्वजनिक नीति पर काफी दवाब डालते हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिका इनके नियंत्रण में रहता है, अतः व्यापारिक दृष्टिकोण के प्रचार व प्रसार में कोई बाधा नहीं होती। समाचार एजेन्सियाँ, संसद-सदस्य, सचिवालय में नियुक्त उच्च अधिकारी भी व्यापारिक घरानों से पूर्णतया प्रभावित हैं। राजनीतिक दलों का विपुल आर्थिक सहायता देकर व्यापारी की सरकार पर अपना प्रभाव डालते हैं।

(ii) **सामुदायिक संघ** — सामुदायिक संघों में धर्म, भाषा, जाति, कबीलों के विभाजन, संघर्षों आदि पर आधारित इनसे प्रेरित दवाब एवं हित समूहों सम्मिलत हैं। चूंकि क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद भारतीय राजनीतिक समुदाय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये गंभीर चुनौती है, अतः इन पर आधारित हित समूह देश के लिये स्वस्थ्य नहीं हैं। जिस प्रकार मुस्लिम लीग ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक पृथक इस्लामी राज्य की मांग की और इसे लेकर रही, सिखों का अकाली दल भी स्वतंत्र भारत में एक पंजाबी सुबा लाने में सफल रहा, GNLF गोरखालैंड के

Scanned with CamScanner

काफी हद तक स्वायत्त बनाने में सफल रहा, उसी प्रकार अन्य दवाब समूह जैसे नागाओं द्वारा स्वतंत्रता की मांग आदि की मांग निश्चित रूप से देश की एकता व अखंडता के लिये खतरनाक है। अतः इनके बढ़ते हुए दवाब समूह को रोकना ही देश के लिए हितकर है।

(iii) **ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ** — अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी श्रमिक संघ बहुत अधिक राजनीतिक रहा है। श्रमिकों की सुधरी हुई कार्य स्थिति और अधिक वेतन के लिये श्रमिक संघों ने अपनी मांगें निजी मैनगमेंट की तुलना में सरकार के समक्ष अधिक स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत किया है। आज राजनीतिक दलों में वृद्धि के साथ-साथ (Trade Unions) में भी वृद्धि हो रही है परन्तु श्रमिक आंदोलन में एकता की कमी है तथा श्रमिक वर्ग का एक छोटा वर्ग ही इसमें शामिल है जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता काफी सीमित हो गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संघों के मध्य आपसी झगड़े एवं मतभेद भी रहते हैं।

फिर भी, आर्थिक स्रोतों की कमी के बावजूद भारत में श्रमिक आंदोलनों एवं संघों ने नीति निर्धारण पर दवाब डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

(iv) **विद्यार्थी संगठन** — आज भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक विद्यार्थी समूह हैं और स्थानीय स्तर के विद्यार्थी समूह उच्चतर विद्यार्थी समूहों से सम्बन्ध हैं। छात्रों की अलग-अलग UNIONS भी हैं जो परस्पर सहयोग भी करती हैं और विरोध भी। राजनीतिक दल इन छात्र संगठनों की सहायता करते हैं।

(v) **भारत में शिक्षित वर्ग के प्रमुख व्यवसाय** — अन्य देशों की भांति भारत में भी शिक्षित वर्गों का विभिन्न दवाब समूह है जैसे All India Medical Council, प्राध्यापकों का FUSTAB, AIFUCTO आदि।

(vi) **महिला संगठन** — महिलाओं का दवाब समूह और संगठन भारत में सक्रिय है। "All India Womens Conference की शाखायें देश भर में फैली हुई है। पहले इस पर साम्यवादियों का प्रभाव था किन्तु अब यह कांग्रेस से सम्बद्ध है। "Hindu Code Bill पर विचार होते समय इस सम्मेलन के एक दवाब समूह के रूप में बड़ा सक्रिय कार्य किया था।

(vii) **सांस्कृतिक समूह** — स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक सांस्कृतिक समूह विकसित हुए। भारत से सांस्कृतिक मंडल विदेशों में जाते रहे हैं और विदेशों से भारत में आते रहे हैं। इस प्रकार के संगठनों का अप्रत्यक्ष रूप से

Scanned with CamScanner

विदेशी सहायता मिलती है और ये देश की राजनीति पर प्रभाव डालने ने प्रयत्नशील हैं।

(viii) **गांधीवादी संगठन** — गांधीवादी संगठन या दवाब समूह नशाबंदी, बुनियादी शिक्षा, सामाजिक नीतियों आदि के सम्बन्ध में सरकार पर निरंतर दवाब डालते रहते हैं। तालीमी संघ, भूटान आंदोलन आदि गांधीवादी संगठन है।

भूमिका (Role) — यद्यपि भारत में दवाब समूहों के विकास की प्रक्रिया धीमी रही है फिर भी ये समूह Masses और Elite के बीच Link का तथा संचार का साधन हैं। यह बढ़ती हुई हिस्सेदारी के लिये अवसर प्रदान करता है।

दवाब समूह सामाजिक एकता बनाने में विशेष योगदान देता है। व्यक्ति को संकुचित दायरे से बाहर कर सामान्य हितों को प्रकट करने के लिये उन्हें आधुनिक और नये संगठनों में लाकर ये समूह न केवल Masses और Elite के बीच की खाई को पाटता है बल्कि समाज के विभिन्न परम्परागत वर्गों को जोड़ता है। इस प्रकार, दवाब समूह Horizontal और Vertical दोनों स्तरों पर एकता कायम करता है।

दवाब समूह केवल अपने हितों को सुस्पष्ट करने का ही कार्य नहीं करता है बल्कि अपने सदस्यों में चेतना, जागृति पैदा करने, राजनीति में उनके भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लोकतांत्रिक दायितव को भी निभाते हैं।

मूल्यांकन — इस प्रकार, दवाब समूह का काफी महत्व है परन्तु भारत में इसके विकास की प्रक्रिया धीमी है तथा यह अन्य पश्चिमी देशों के दवाब समूहों की तुलना में उतनी प्रभावशाली नहीं है। भारत में क्षेत्रीय दलों के रूप में दवाब समूहों का उदय अत्यन्त खतरनाक है, देश की एकता के लिये। आज भारतीय समाज में जिस ढंग से ये पनप रहे हैं और अपनी मांगों के मनाने में यह हिंसा का सहारा ले रहे हैं, यह निश्चित ही देश की एकता एवं अखंडता को कमजोर करेगा। अकालियों द्वारा खालिस्तान की मांग, कश्मीरी मुसलमानों द्वारा पृथक कश्मीर की मांग GNLF द्वारा पृथक गोरखालैंड की मांग इन सभी पर अंकुश रखने की आवश्यकता है।

Robert L. Hardgrave के शब्दों में, "No Political System can be satisfying for all the demands of all its members all the time." इसलिये दवाब समूहों की आवश्यकता होती है और उनका प्रभाव पड़ता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था पर। भारत इससे अछूता नहीं है। Hardgrave के अनुसार, "In India there is a basic distruct of Politics as a struggle for power."

Scanned with CamScanner

(7)

दवाब समूह की भूमिका भारत के विशेष संदर्भ में

इस कारण से भारतीय राजनीति में 'Arenas of Conflicts' काफी हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम इन दवाब समूहों को, Hardgrave के अनुसार, "Reservoirs of Political leadership" के रूप में भी देखते हैं।

ये सभी कारण भारत में दवाब समूह की राजनीति का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लाभकारी सिद्ध कर रहे हैं।

Stop

Scanned with CamScanner